

**प्रमुख वित्तीय संकट**

महामंदी से व्यापक अपगमन

श्री वी. श्रीनिवास, आईएस  
अध्यक्ष, राजस्थान राजस्व बोर्ड

**प्रमुख वित्तीय संकट**

महामंदी से व्यापक अपगमन

यह लेख भारतीय बैंकिंग के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित सदस्य डा. नरसिंहम, डा. सी. रंगराजन, डा. विमल जालान, डा. वाई. वी. रेड्डी और डा. डुवुरी सुब्बाराव को समर्पित है। इन महान व्यक्तियों ने राष्ट्र की बृहत आर्थिक नीतियों की भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में देख-रेख की और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का दृढ़तापूर्वक समाधान किया तथा अर्थव्यवस्था को कई प्रतिकूल परिस्थितियों से निकालकर दूरदृष्टि के साथ पटरी पर ले आए जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था को कई तूफानों से होकर गुजरना पड़ा।

**सार**

राष्ट्रों के आर्थिक इतिहास में उनके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों की अनेक सफल कहानियां हैं लेकिन इनमें आर्थिक संकट के दौरान करोड़ों लोगों द्वारा सामना किए गए उन कठिनाई से भरे वर्षों को सबसे अधिक याद किया जाता है।

विश्व आर्थिक इतिहास प्रमुख वित्तीय संकट पर व्याख्यान में 7 प्रमुख वित्तीय संकटों को कवर किया जाएगा जिनसे होकर विश्व को पिछले 100 वर्षों में गुजरना पड़ा है। प्रस्तुत किए जाने वाले 7 संकट निम्नलिखित हैं, महामंदी 1932, स्वेज संकट 1956, अंतरराष्ट्रीय ऋण संकट 1982, पूर्व एशियाई आर्थिक संकट 1997-2001, रूसी आर्थिक संकट 1992-1997, मेक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना में लैटिन अमेरिकी ऋण संकट 1994-2002 और वैश्विक आर्थिक अपगमन 2007-09

**सार**

- महामंदी, स्वेज संकट, अंतरराष्ट्रीय ऋण संकट, पूर्व एशियाई संकट, लैटिन अमेरिकी ऋण संकट और व्यापक अपगमन ऐसी घटनाएं थीं जिनमें कई देशों ने एक साथ संकट महसूस किया। प्रत्येक घटना में, वैश्विक संकट से पहले अत्यधिक वृद्धि दरें और वित्तीय उथल-पुथल के वर्ष में आर्थिक विफलता देखने को मिली।

**महामंदी 1932**

- 25 दिसम्बर, 1929 को न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज में घबराहट में बिक्री के फलस्वरूप 13 मिलियन शेयरों की बिक्री होते हुए देखा गया।
- 1920 के दशक के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 1922 से 1929 तक स्टॉक मार्केट के मूल्यों में 7 वर्षों के लिए 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 218 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। किसी भी देश ने स्टॉक की कीमतों में ऐसा उछाल कभी नहीं देखा जिसके फलस्वरूप करोड़ों अमेरिकी वित्तीय सट्टेबाजी की ओर आकृष्ट हुए।
- किसी भी व्यक्ति ने संभावित स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं देखा था और इसके होने से पहले अमेरिकी इसे स्थायी समृद्धि मान चुके थे। अक्टूबर, 1929 में अमेरिकी मार्केटों के विध्वंस के लिए कोई यौक्तिक स्पष्टीकरण नहीं था।

**महामंदी 1932**

- लगभग 30 बिलियन अमेरिकी डालर का एक दिन में नुकसान हुआ और हजारों निवेशक बरबाद हो गए। अमेरिकी शेयर बाजार के गिरने के पश्चात वर्ष 1931 में कई बैंकों में घबराहट उत्पन्न हो गई और यह वित्तीय बीमारी यूरोप शुरू होकर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस में फैल गई तथा अंततः पूरा विश्व महामंदी की चपेट में आ गया। यह महामंदी 1929 से लेकर 1939 तक रही और इतिहास में यह सबसे बुरी मंदी थी।

- 1933 तक, 15 मिलियन अमेरिकी बेरोजगार हो गए, 20,000 कंपनियां दिवालिया हो गईं और बड़ी संख्या में अमेरिकी बैंक बंद हो गए।

166

### महामंदी 1932

1928 के प्रारंभ में अमेरिका में महत्वपूर्ण चालू खाता अधिशेष और जर्मनी में पर्याप्त चालू खाता घाटा कायम रहा। जर्मनी के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा अमेरिका से डालर के मूल्यवर्ग में बांड और ऋणों के जरिए विदेशी मुद्राओं के उधार नीदरलैंड, स्विटजरलैंड और ऑस्ट्रिया के बैंकों के माध्यम से लिए गए।

अमेरिका में मौद्रिक संकुचन से जर्मनी में मंदी आई। रीक्सबैंक के सोने और विदेशी मुद्रा के विदेशी भंडारों में बड़ी तीव्र गिरावट आई।

167

### महामंदी 1932

- मई 1931 में ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा बैंक क्रेडिटान्स्टाल्ट धराशायी हो गया।
- चूंकि निवेशकों में यह भय व्याप्त हो गया कि उनके पैसा अवरुद्ध हो जाएगा या उनको पैसों की हानि हो जाएगी, अतः लोगों ने बैंकों से अपना सारा पैसा निकालना शुरू कर दिया। जर्मनी को इस संकट को रोकने के लिए आवश्यक विदेशी ऋण नहीं मिला। पूंजी के बहिर्प्रवाह को रोकने के लिए जर्मनी को बैंक बंद करने पड़े, मार्क का मूल्य करना पड़ा, विदेशी ऋणदाताओं के साथ रूके करारों पर बातचीत करनी पड़ी और मुद्रा पर नियंत्रण करना पड़ा।
- 1930-32 की अवधि में, अमेरिका में मुद्रा आपूर्ति 26 प्रतिशत, जर्मनी में 27 प्रतिशत, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में 18 प्रतिशत कम हो गई।

168

### महामंदी 1932

- जर्मन मुद्रा और बैंकिंग संकट का ब्रिटिश पाउंड पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यूरोपीय बैंक जिनकी परिसंपत्तियों को जर्मन स्टैंडस्टिल करारों द्वारा अवरुद्ध किया गया था, अपना पैसा यूनाइटेड किंगडम से अत्यधिक मात्रा में निकाल रहे थे जिसके परिणामस्वरूप पाउंड कमजोर हो गया। 16

सितम्बर, 1931 को यूनाइटेड किंगडम ने सोने की परिवर्तनीयता को रोक दिया और पाउंड को फ्लोट होने दिया।

- 1933 तक 35 राष्ट्रों ने सोना और सोने से अदला-बदली के मानकों को छोड़ दिया। 1932 में निर्यात के मूल्य में विगत वर्ष से यूनाइटेड किंगडम के 7 प्रतिशत और कनाडा के 19 प्रतिशत की तुलना में फ्रांस में 35 प्रतिशत, जर्मनी में 40 प्रतिशत और अमेरिका में 33 प्रतिशत की गिरावट आई।

169

### महामंदी 1932

- अप्रैल और मई 1933 के दौरान अमेरिका में तीव्र औद्योगिक उछाल के साथ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिक गतिविधि के रूप में आर्थिक सुधार दिखाई पड़ा।
- राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की 'नई डील' से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार आया, बेरोजगारों को अमेरिकी कल्याणकारी स्टेट – संघीय सहायता, उद्योग का कठोर विनियमन, कामगारों के लिए कानूनी सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की नींव पड़ी।
- 'नई डील' अमेरिका के महामंदी से ताकतवर देश के रूप में उभरने का पहला कदम था और देश की स्वतंत्र विश्व के निर्विवाद नेता बनने की शुरुआत थी।

170

### स्वेज संकट

- 26 जुलाई, 1956 इजिप्त ने स्वेज कनाल कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। फ्रांस, इजराइल और यूनाइटेड किंगडम ने 29 अक्टूबर, 1956 को सिनई पर आक्रमण करके इजराइल के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई शुरू की। यह सैन्य कार्रवाई दो माह चली और उथल-पुथल और अनिश्चितता के दौर में एक वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ।
- सभी चार देश शीघ्र ही आईएमएफ की वित्तीय सहायता की मांग करने लगे। इससे कई राजनीतिक परिणाम भी सामने आए। इजिप्त को स्वतंत्रता मिली, इजराइल राष्ट्र के रूप में कायम रहा और ब्रिटेन की विजयी रथ में विराम लग गया। स्वेज नहर 6 माह के लिए बंद रहा जिसके परिणामस्वरूप व्यापार के मार्ग में बदलाव, लागत में बढ़ोतरी और डिलिवरी में विलंब हुआ जिससे सभी चार देशों के चालू खाता शेष पर बड़ा प्रभाव पड़ा।

## स्वेज संकट

- सितम्बर-अक्तूबर 1956 में इजिप्ट, इजराइल और फ्रांस ने चालू खाता से उत्पन्न होने वाली भुगतान शेष की अस्थायी समस्याओं से निजात पाने के लिए वित्तपोषण संबंधी अनुरोध के साथ आईएमएफ से संपर्क किया।
- 1956 में ब्रिटेन के पास काफी बड़ा चालू खाता अधिशेष था। पाउंड स्टर्लिंग भारी अनिश्चित दबाव में आया और यूनाइटेड किंगडम में अल्पावधिक पूंजीगत बहिर्प्रवाह देखा गया।
- यूनाइटेड किंगडम आईएमएफ से वित्तीय सहायता के लिए योग्य नहीं पाया गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास आईएमएफ सहायता के बिना ऋण प्रदान करने और बहिर्प्रवाह को प्रबंध करने के पर्याप्त संसाधन थे। आईएमएफ ने सभी 4 देशों को स्टैंड बाई आधार पर वित्तपोषण प्रदान किया। इस कार्य से आईएमएफ को अंतरराष्ट्रीय संकट प्रबंधक की भूमिका मिली। स्वेज संकट युद्ध पश्चात युग का पहला प्रमुख वित्तीय संकट था।

## स्वेज संकट

- सितम्बर 1956 तक फ्रांस में निम्न एवं घटते विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति देखी गई। फ्रेंच फैंक फ्लाइट ऑफ कैपिटल के अधीन था। फ्रांस ने 263.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कोटे के 50 प्रतिशत की वित्तीय व्यवस्था की मांग की।
- 1956 में फ्रांस के चालू खाता की स्थिति 1.1 बिलियन बिगड़ कर 409 मिलियन अमेरिकी डॉलर अधिशेष से 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर घाटे में परिवर्तित हो गई। अक्तूबर, 1956 में आईएमएफ ने फ्रांस के वित्तीय अनुरोध को अनुमोदित कर दिया।

## स्वेज संकट

- इजिप्ट आईएमएफ से दूसरी बार ऋण ले रहा था। यह 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तपोषण संबंधी अनुरोध था और राजनीति ने इजिप्ट के आईएमएफ वित्तपोषण में कोई घुसपैठ नहीं की।

- इजराइल 1954 में आईएमएफ में शामिल हुआ। इजिप्ट से एकाकी रूप से तटस्थ रहने के साथ आईएमएफ ने 15 मई, 1957 को इजराइल के वित्तपोषण के लिए इसके कोटे के 50 प्रतिशत का अनुमोदन कर दिया।

174

### स्वेज संकट

- ब्रिटेन के पास काफी बड़ा चालू खाता अधिशेष था और आईएमएफ में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोटा था। बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास अमेरिकी डॉलर के प्रति 2.80 अमेरिकी डॉलर की समानता थी और अनिश्चितता को देखते हुए स्टर्लिंग समानता को छोड़ने का दबाव था। ब्रिटेन ने 2.80 अमेरिकी डॉलर को व्यापार प्रयोजनों के लिए उचित माना और विनिमय दर स्थिरता को तरजीही व्यापार क्षेत्र और आरक्षित मुद्रा के रूप में स्टर्लिंग क्षेत्र को परिरक्षित करने हेतु अनिवार्य समझा। ब्रिटेन 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के न्यूनतम शेष का भंडार रखना चाहता था।
- चूंकि बाजार संवेदनाएं पाउंड स्टर्लिंग के विरुद्ध हो चुकी थीं, अतः ब्रिटिश प्राधिकारी जानते थे कि वे अमेरिका की सहायता के बिना पाउंड को 2.80 अमेरिकी डॉलर प्रति डॉलर पर रोक कर नहीं रख सकते हैं। ब्रिटेन को पाउंड के विरुद्ध अनिश्चितता को दूर करने हेतु 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता पड़ी।

175

### अंतरराष्ट्रीय ऋण संकट

- अंतरराष्ट्रीय ऋण संकट 20 अगस्त, 1982 को शुरू हुआ।
- मेक्सिको उस ऋण की भुगतान वापसी नहीं कर पाया जो देय था और यह संकट 20 देशों को निगल गया। यह एक दशक तक चले अंतरराष्ट्रीय ऋण संकट की शुरुआत थी।
- मार्च, 1981 में पौलैंड ने अपने बैंक ऋणदाताओं को सूचना दी कि वह अपने ऋण दायित्वों की भुगतान वापसी नहीं कर सकता है। पौलैंड के बाद अनेक अन्य देश भी इस संकट में आए – रोमानिया, हंगरी और युगोस्लाविया ने भी भुगतान वापसी की शर्तों में परिवर्तन हेतु अनुरोध किया है।
- 1970-80 की अवधि में अमेरिका में हुए मौद्रिक संकुचन के परिणामस्वरूप अमेरिकी डॉलर में स्थायी बढ़ोतरी हुई। इससे पूर्वी यूरोप और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों के लिए डॉलर में भुगतान वापसी करना असंभव हो गया। वाणिज्यिक ऋण संकट 1982 में शुरू हुआ और 1989 तक चला।

### अंतरराष्ट्रीय ऋण संकट

- सत्तर के दशक में विकासशील देशों ने तीव्रता से विकास कर रहे अंतरराष्ट्रीय ऋण बाजारों से कम ब्याज दरों पर खुलकर उधार लिया। बैंक तेल निर्यातक देशों से बड़ी जमाराशि लेकर नकदी के मामले में धनी हो गए और तेल आयातक देशों को काफी ऋण प्रदान किया। ऋणों का उपयोग निवेश परियोजनाओं या वर्तमान खपत को बढ़ाने पर किया गया। अनेक विकासशील देशों ने अपनी राष्ट्रीय आय के 12 प्रतिशत तक उधार लिया जिसके परिणामस्वरूप ऋण शोधन कठिनाइयां मुख्य रूप से हुईं।
- वाणिज्यिक बैंकों को यह लगा कि विकासशील देशों को सार्वभौम ऋण प्रदान करना एक अत्यधिक लाभदायक गतिविधि है। मेक्सिको और पोलैंड में संभावित संकट सर्वप्रथम प्रकट हुआ। इसके ठीक बाद मेक्सिको, लैटिन अमेरिका के अनेक देश – अर्जेंटिना, ब्राजील, चिली, इक्वेडोर, पेरू और उरुग्वे को ऋण-शोधन संबंधी समस्याएं हुईं।

### अंतरराष्ट्रीय ऋण संकट

- अंतरराष्ट्रीय ऋण संकट 1981 से 1989 तक चला। इसने पूरे विश्व में लगभग 20 देशों को 30 विभिन्न घटनाओं के साथ चपेट में लिया। प्रभावित 3 प्रमुख पूर्वी देशों में पोलैंड, रोमानिया और हंगरी तथा प्रभावित 3 प्रमुख लैटिन अमेरिकी देशों में चिली ..... शामिल थे।
- प्रत्येक देश में गंभीर ऋण समस्याओं का सामना किया परंतु प्रत्येक देश की उत्पत्ति और निहितार्थों में अलग-अलग समस्या थी। अधिकांश अत्यधिक ऋणग्रस्त देशों में दीर्घावधिक विकास के लिए नवाचार और व्यापक कार्यनीति का आवश्यकता पड़ी। ऋणग्रस्त देशों की विकास संभावनाओं को सुदृढ़ करने के लिए बेकर योजना और इसके बाद ब्रैडी योजना तैयार की गई।

### अंतरराष्ट्रीय ऋण संकट

- 1982-89 के अंतरराष्ट्रीय ऋण संकट का समाधान त्रिभुज कार्यनीति के जरिए किया गया –
- वाणिज्यिक बैंकों का सामूहिक हित था, ऋणदाता देशों का सामूहिक हित था और समन्वयन प्रयासों की अगुवाई एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने की।
- ऋण शोधन कठिनाइयों के होने के बावजूद सर्वांगी संकट 1983 तक धीरे-धीरे कम हो गया। 1985-87 की अवधि स्थायी विकास की अवधि थी और विकासशील देश ऋण शोधन के भार को कम कर पाए।
- 1989 तक कई ऋणग्रस्त देशों द्वारा सामना किए जाने वाले बाह्य आर्थिक वातावरण में महत्वपूर्ण सुधार हुआ जिससे अंतरराष्ट्रीय ऋण संकट दूर हुआ।

### अंतरराष्ट्रीय ऋण संकट

- एक प्रमुख आर्थिक संकट ने 1997 में कई पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया। पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाएं – जिनमें जीविका के स्तर में तीव्र विकास और सुधार हो रहा था, एक गंभीर वित्तीय संकट में उलझ गईं। अप्रतिम आर्थिक विकास, समृद्धि एवं आशा के दशक में व्यवधान डालते हुए इस संकट ने क्षेत्र में आर्थिक अभिशासन की प्रणालियों की अनिश्चितता को उजागर कर दिया।
- यह संकट अत्यधिक बाह्य घाटों, संपत्ति एवं शेयर बाजार के बढ़े हुए मूल्यों, घटिया विवेकपूर्ण विनियमन, पर्यवेक्षण की कमी और विदेशी मुद्रा दर में डॉलर के बढ़ने से हुआ और परिणामस्वरूप विनिमय दरों में भारी उतार-चढ़ाव से अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता अस्थायी हो गई।

### पूर्वी एशियाई संकट

- दक्षिण पूर्व एशियाई मुद्रा में गिरावट थाइलैंड – में शुरू हुई। थाइलैंड का चालू खाता घाटा और विदेशी ऋण दायित्वों पर ब्याज थाइलैंड के जीडीपी के 4 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया था।
- ऋणदाताओं को यह लगा कि थाइलैंड के खड़े चालू खाता घाटे से उच्च व्यापारिक निवेश होता है क्योंकि इसमें उच्च बचत दरें और सरकारी बजट अधिशेष शामिल होता है।

- थाइलैंड ने डॉलर के सापेक्ष नियत विनिमय दर कायम रखी। थाई बाहट जमाराशियों पर उच्च ब्याज दरें और 25 बाहट प्रति डालर की नियत विनिमय दर को देखते हुए विदेशी निधियां थाइलैंड में आती रही।

181

### पूर्वी एशियाई संकट

- परंतु, बाहट का डालर के प्रति नियत मूल्य स्थायी नहीं रह सका। 1996 और 1997 में जापानी येन डालर के मुकाबले 35 प्रतिशत गिर गया। डॉलर/येन की विनिमय दर में व्यापक उतार-चढ़ाव से अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता जो अस्थायी रही, में बदलाव के जरिए संकट बढ़ा। जब विदेशी निवेशकों ने बाहट को बेचना शुरू किया तो सरकार इसके मूल्य को सहारा देने के लिए आगे आई। तथापि, यह मुद्रा स्थायी न रह सकी और अंततः थाई मुद्रा धराशायी हो गई।

182

### पूर्वी एशियाई संकट

- जब वित्तीय निवेशक बड़े चालू खाता घाटे के बारे में चिंतित हो गए, तो इस रोग ने इंडोनेशिया और कोरिया को घेर लिया। 2 जुलाई, 1997 को थाई बाहट फ्लोट करने लगा और 15-20 प्रतिशत गिर गया। 24 जुलाई, 2017 को पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया रुपया, थाई बाहट और मलेशियाई रिंगिट पर भारी दबाव के साथ 'मुद्रा में भारी गिरावट' देखी गई।
- 1997 के इंडोनेशिया आर्थिक संकट से 30 वर्ष के अबाधित आर्थिक विकास पर विराम लग गया और 20वीं सदी में विश्व के किसी देश को होने वाला सबसे बुरा संकट रहा।

183

### पूर्वी एशियाई संकट

- इंडोनेशियाई रुपिया सन्निकट उच्च मुद्रास्फीति और वित्तीय मंदी के साथ मई 1997 के 2500 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर से जनवरी 1998 में लगभग 14000 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर हो गया। 16 बैंकों के बंद हो जाने से भय उत्पन्न हो गया। इंडोनेशियाई प्राधिकारियों ने सभी जमाकर्ताओं और ऋणदाताओं के लिए ब्लैकट गारंटी प्रदान करने, इंडोनेशियाई बैंक पुनर्गठन एजेंसी का सृजन और कैरी फॉरवर्ड कॉरपोरेशन रीस्ट्रक्चरिंग के प्रति आश्वासन प्रदान करने के कदम उठाए।

### पूर्वी एशियाई संकट

- 1997 में कोरिया 5 प्रतिशत से कम मुद्रास्फीति दर, 3 प्रतिशत से कम बेरोजगारी दर और 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की जीडीपी वृद्धि के साथ विश्व में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में था। कोरियाई आर्थिक संकट इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि इसकी व्यापारिक और वित्तीय संस्थाओं ने लगभग 110 बिलियन अमरीकी डालर का अल्पावधिक विदेशी ऋण लिया था जो इसके विदेशी मुद्रा भंडारों का तीन गुणा था। बड़ी मात्रा में वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ी क्योंकि देशों ने निजी ऋणदाताओं को ऋण भुगतान करना रोक दिया। कोरियाई वॉन अत्यधिक दबाव में आ गया और कोरिया को आईएमएफ सहायता लेनी पड़ी। कोरिया को 57 बिलियन अमरीकी डालर आईएमएफ कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ी और इंडोनेशिया को 40 बिलियन अमेरिकी डालर के आईएमएफ कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ी।

### पूर्वी एशियाई संकट

- इंडोनेशिया, थाइलैंड और कोरिया में आईएमएफ कार्यक्रमों की सामाजिक लागत अत्यधिक थी। विनिमय दर की बड़ी गिरावट के परिणामस्वरूप उपर्युक्त तीनों देशों में कीमतों में तीव्र गिरावट देखी गई और बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए। खाद्य पदार्थों की कीमतें 35 प्रतिशत तक बढ़ गईं। बेरोजगारी का स्तर इंडोनेशिया में 12 प्रतिशत, कोरिया में 9 प्रतिशत और थाइलैंड में 8 प्रतिशत बढ़ गया। संकट वाले इन तीनों देशों में से केवल कोरिया के पास औपचारिक बेरोजगारी बीमा था, अन्य दो देशों में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाएं - उपलब्ध नहीं थी।

### पूर्वी एशियाई संकट

- आईएमएफ कार्यक्रमों ने वित्तीय संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्पूजीकरण को बढ़ावा दिया। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अभिशासन मॉडलों में पारदर्शिता और जबाबदेही के सुदृढीकरण से सुधार हुआ। आईएमएफ के कार्यक्रमों में राजकोषीय नीतियों पर फोकस किया गया जिससे देशों की विदेशी बचतों पर निर्भरता में कमी आई और बैंकिंग प्रणालियों के पुनर्गठन और पुनर्पूजीकरण की लागत को ध्यान में रखा गया।

### रूसी संकट

- नब्बे के दशक के मध्य में रूस सोवियत पश्च अवधि से निकलकर बाजार अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा था। बहुत अधिक सामाजिक अव्यवस्था हुई, जीवन स्तर में गिरावट आई और मुद्रास्फीति 300 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई। कई रूसी व्यक्तियों के पास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं हेतु बचत राशि भी नहीं थी। अर्थव्यवस्था के विभिन्न भागों में वस्तु विनिमय प्रणाली व्याप्त थी। ऋण की भुगतान वापसी या विधिक प्रवर्तन की व्यवस्था की जानी थी। मुद्रास्फीति का मुख्य कारण राजकोषीय अनुशासन में कमी था - सरकार को सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया द्वारा वित्तपोषित बजट में अत्यधिक घाटा हो गया था। बड़े पैमाने पर कर अपवंचन और पूंजी का नुकसान हो गया था।

### रूसी संकट

1995 में बजट घाटे को कम करने के लिए कमजोर प्रयास किए गए। सरकार अमेरिकी डॉलर की तुलना में रूबल की विनिमय दर को पूर्व घोषित बैंड के भीतर रखकर धन वृद्धि पर नियंत्रण रखना चाहती थी। इस प्रकार विनिमय दर को कायम रखने के लिए धन वृद्धि पर नियंत्रण किया गया।

1996 तक मुद्रास्फीति को 50% से कम पर और एशियाई संकट के प्रारंभ तक 15% से कम स्तर पर लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और विदेशियों द्वारा अर्जित सरकारी पत्रों तक रूस की पहुंच हो गई। सुदृढ़ विदेशी चालू खाता, बढ़ते अंतरराष्ट्रीय कोषों और विनिमय दर में बढ़ोतरी से उच्च शोधन लागतों, परिपक्वता की अल्प अवधि की संरचना और विनिमय दर की अचानक गिरावट से राष्ट्र पर हो सकने वाले प्रभावों की चुनौतियां समाप्त हुईं।

### रूसी संकट

- 1997 में पूर्वी एशियाई संकट तेल की कीमतों के कमजोर होने के फलस्वरूप रूस की व्यापार स्थिति में तीव्र और अचानक गिरावट आई। कुल निर्यात में 25% की गिरावट हुई और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी तक पहुंच में बढ़ती लागत के साथ के पूंजी तक पहुंच में बढ़ती लागत पूंजी बाजारों से अंतर्वाह में कमी आई।
- 1997-98 के दौरान गिरती भुगतान शेष स्थिति के साथ रूस ने 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय ऋण की भुगतान वापसी का सामना किया। सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया ने बाजार में दखल दिया और विनिमय दर को बचाने हेतु विदेशी मुद्रा भंडारों की बिक्री की।
- बाजार संवेदनाओं में तीव्र गिरावट हुई और राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से उधार लेने के बावजूद मुद्रा भंडारों की स्थिति में तीव्र गिरावट हुई। यह स्पष्ट था कि रूस में हुए व्यापक विघटन से बचा जा सकता था, यदि सरकार राजकोषीय अनुशासन का पालन करती।

### रूसी संकट

- वित्तीय संस्थाओं के बीच सामंजस्य की कमी थी क्योंकि आई एम एस द्वारा अनुशंसित कार्यक्रम के मुख्य तत्वों को डुमा ने अस्वीकार कर दिया था। रूसी संकट के पहले 6 माह में कोई विश्वसनीय बृहद आर्थिक नीति संबंधी प्रतिक्रिया नहीं हुई।
- फरवरी 1999 तक रूबल के मूल्य में डॉलर के मुकाबले 70% की गिरावट आई और मुद्रास्फीति 90% हो गई। बैंकिंग संकट नहीं हुआ क्योंकि बैंक मुख्य रूप से भुगतान प्रणाली के रूप में कार्य कर रहे थे और उद्यमों के बैलेंस शीट पर संकट का प्रभाव मामूली था।
- रूस ने रूबल के मूल्य वर्ग वाले ऋण और निजी क्षेत्र के बाह्य भुगतानों सहित ऋण शोधन भुगतानों पर समय रूप से निलंबन की घोषणा कर दी।

### रूसी संकट

- अनियंत्रणीय प्रतीत हो रहे विदेशी ऋण की काली छाया और बेकाबू मुद्रास्फीति के खतरे से 1999 रूसी बजट में राजकोषीय अनुशासन की सोच उत्पन्न हुई। 1999 की तीसरी तिमाही तक तेल की कीमतों में सुधार से रूस को अपने भंडारों के तीव्र निर्माण में सहायता मिली। रूस समान अवधि

में संकटग्रस्त अन्य देशों की तुलना में तेल एवं गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण शीघ्रता से संभल पाया।

192

### लैटिन अमेरिकी ऋण संकट

- लैटिन अमेरिकी ऋण संकट कई बार घटित हुआ। 200 वर्ष के इतिहास में वस्तुतः 8 प्रमुख महादेशीय संकट देखा गया। पहला लैटिन अमेरिकी ऋण संकट 1826-1828 में इसके बाद 1873, 1890 और 1931 में संकट हुआ।
- 20वीं शताब्दी में लैटिन अमेरिका में कई संकट देखा गया जो इस प्रकार हैं, 1982 - मैक्सिको की चूक, 1994/95 - टकीला संकट, 2001-02 - अर्जेंटीना की चूक, 1999/03- ब्राजील संकट और 2008/09 - वैश्विक वित्तीय संकट। लैटिन अमेरिका का संकट से भरा इतिहास वित्तीय संकट के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

193

### लैटिन अमेरिकी ऋण संकट

- फरवरी 1995 में मैक्सिको ने 18 माह के कार्यक्रम के लिए 17.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उधत व्यवस्था हेतु आईएमएफ से संपर्क किया। यह किसी सदस्य देश के लिए आईएमएफ द्वारा अनुमोदित अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय पैकेज था। मैक्सिको के वित्तीय संकट को अंतर्राष्ट्रीय प्रत्युत्तर प्रदान करने हेतु विशेष कारवाई और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को विश्वास प्रदान करना आवश्यक था।
- 1994 के दौरान मैक्सिको में नाटकीय प्रतिकूल राजनीतिक घटनाओं की पृष्ठभूमि में चालू खाता घाटे की धारणीयता के बारे में निवेशकों की चिंताएं बढ़नी शुरू हो गईं। पूंजी के बहिर्प्रवाह को रोकने के लिए प्राधिकारियों ने ब्याज दरें बढ़ा दी और पैसे का मूल्य कम कर दिया।
- इसके बावजूद विदेशी भंडारों को काफी नुकसान हुआ विदेशी मुद्रा पर अत्यधिक दबाव पड़ा तथा वित्तीय बाजारों में वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ। मैक्सिकन वित्तीय संकट से कई अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में वित्तीय और मुद्रा बाजारों पर गंभीर दबाव पड़ा।

### लैटिन अमेरिकी ऋण संकट

- 1998 में पूर्वी एशियाई संकट के पश्चात ब्राजील पर काफी दबाव पड़ा क्योंकि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वातावरण के नाटकीय रूप से बिगड़ जाने के परिणामस्वरूप यह रोग उत्पन्न हुआ। ब्राजिलियाई प्राधिकारियों ने आपातकालीन राजकोषीय और मौद्रिक नीतिगत उपाय किए - राजस्व में बढ़ोतरी की और व्यय में जीडीपी के 2% प्रतिशत के समतुल्य कटौती की तथा घरेलू ऋण दरों को बढ़ाकर 43% प्रतिशत कर दिया।
- अगस्त, 1998 तक पूंजी खाते पर रूसी संकट के पश्चात गंभीर दबाव पड़ा और अतिरिक्त व्यय कटौती और राजकोषीय सुदृढीकरण उपाय करने पड़े। इन उपायों के बावजूद विदेशी मद्रा भंडार जुलाई से अक्टूबर 1998 तक के 3 माह में 70 बिलियन अमेरिकी डालर से गिरकर 45 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया और ब्राजील को एक प्रमुख आर्थिक पुनर्गठन कार्यक्रम की आवश्यकता हुई।
- ब्राजील ने 36 माह के लिए 18 बिलियन अमेरिकी डालर की उधत व्यवस्था के लिए आईएमएफ को संपर्क किया। यह कार्यक्रम निवारक स्वरूप का था जिसका उद्देश्य ब्राजील को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों की विकट अनिश्चितता की अवधि का सामना करने में सहायता करना था।

### लैटिन अमेरिकी ऋण संकट

- 2001-2002 में अर्जेन्टिना ने अपने इतिहास में सबसे बुरा आर्थिक संकट देखा। जीडीपी 3 वर्षों में 20 प्रतिशत तक गिर गया। मुद्रास्फीति काफी अधिक बढ़ गई, अर्जेन्टिना ने अपने प्रमुख ऋण को चुकाने में चूक कर दी, बैंकिंग प्रणाली चरमरा गई और अर्जेन्टाइन पेसो जो अमेरिकी डालर के बराबर था जून 2002 में अमेरिकी डालर के मुकाबले 3.90 अर्जेन्टाइन डालर पर आ गया।
- एक वर्ष से भी कम समय पहले अर्जेन्टिना सफल आर्थिक सुधार के मॉडल के रूप में जाना जाता था, मुद्रास्फीति एकल अंकों में थी, जीडीपी वृद्धि प्रभावशाली थी और अर्थव्यवस्था ने टकीला संकट से अपना बचाव सफलतापूर्वक किया था। अर्जेन्टिना 21वीं शताब्दी के आर्थिक अभिशासन का मॉडल सुधारक माना जाता था।

### लैटिन अमेरिकी ऋण संकट

- 2002 का अर्जेन्टिना संकट बृहत वित्तीय घाटों और अति मुद्रास्फीति के कारण नहीं बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण संबंधी गति विज्ञान में आई दुर्बलता के कारण हुआ। मुद्रा बोर्ड संबंधी व्यवस्था ने बजट घाटों के प्रत्यक्ष धन वित्तपोषण को रोक दिया। संकट को दूर करने में कीमत में गिरावट आई और बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ और अच्छी तरह पूंजीकृत प्रतीत हुई।
- अर्जेन्टिना मौद्रिक नीति व्यवस्था में फंसा दिखाई पड़ा जिससे नीतिगत चयन में रुकावट आई।

### लैटिन अमेरिकी ऋण संकट

- बढ़ता राजकोषीय घाटा, सरकार के उच्च बजट कार्यकलापों और संघीय बजट से कार्यक्षेत्रों को तथा ब्याज वापसी में 30 प्रतिशत से अधिक अंतरण से अर्जेन्टिना के नीतिगत विकल्पों में अत्यधिक बाधाएं आईं। अर्जेन्टिना की अर्थव्यवस्था में निर्यात का हिस्सा सीमित हो गया और देश संकट के कारण पर्याप्त निर्यात नहीं कर पा रहा था। ऋण शोधन भुगतानों में निर्यात अर्जन का 3/4वां भाग खर्च हो रहा था। नाटकीय रूप से बढ़ते ऋण की स्थिति में मुद्रा की भारी गिरावट को देखते हुए अर्जेन्टिना ने सरकारी ऋण के भुगतान में चूक कर दी और मुद्रा बोर्ड धराशायी हो गया।

### लैटिन अमेरिकी ऋण संकट

- अर्जेन्टिना संकट के लिए आईएमएफ की 14 बिलियन अमेरिकी डालर की उद्यत व्यवस्था और 40 बिलियन अमेरिकी डालर के अंतरराष्ट्रीय सहायता पैकेज की आवश्यकता थी। बृहत् आर्थिक स्थिरीकरण कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के अधिशेष को जीडीपी के 1/2 प्रतिशत से बढ़ाकर जीडीपी के 1 प्रतिशत करने का और राजकोषीय घाटे को जीडीपी के (-) 6.4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत करने की योजना थी। इन उपायों के बावजूद जीडीपी वृद्धि में गिरावट होती रही और 2002 में यह गिरकर 11 प्रतिशत हो गया तथा बेरोजगारी विकट मुद्रास्फीति के साथ 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई। अर्जेन्टिना ने शून्य घाटा कानून पारित किया और नीतियों में आमूल चूल परिवर्तन किए क्योंकि इसके निधिपोषण विकल्प समाप्त हो चुके थे।

### व्यापक अपगमन

- 2008 में अमेरिका और यूरोप में गंभीर अपगमन हुआ जो 1930 से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था का अब तक की सबसे बड़ा अपगमन था और विश्व युद्ध के बाद की अवधि से पहला वार्षिक संकुचन था। वित्तीय संकट जो 2007 में अमेरिकी उप-प्रमुख संकट के साथ आरंभ हुआ, गहराता गया और 2008 तक काफी उग्र चरण में पहुंच गया।
- इसका प्रभाव उभरते बाजारों के साथ-साथ पूरे वैश्विक वित्तीय तंत्र में महसूस किया गया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उभरते और विकासशील व्यवस्थाओं के बढ़ते एकीकरण पर स्थायी विस्तार के वर्षों के पश्चात् 2008 में वैश्विक आर्थिक निष्पादन में गिरावट हुई। शिथिल विनियामक और बृहत् आर्थिक नीतियों से वित्तीय, आवास एवं पण्य बाजारों में असंतुलन उत्पन्न हुआ। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली तबाह हो गई।

### व्यापक अपगमन

अमेरिका का जीडीपी 2008 की चौथी तिमाही में उच्चतम अमेरिकी शेयर बाजार सूचकांक में साथ लगभग 4 प्रतिशत गिर गया, एस एंड पी 500 अपने 2007 के उच्च स्तर से 45 प्रतिशत गिर गया। वैश्विक जीडीपी वृद्धि 2007 के 5 प्रतिशत से गिरकर 2008 में 3¼ प्रतिशत और 2009 में 2 प्रतिशत हो गई। आईएमएफ ने वैश्विक वित्तीय संस्थाओं की 1.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर की ऋण संबंधी हानि का अनुमान लगाया। लेहमन ब्रदर्स सितम्बर 2008 में धराशाई हो गया।

ऋण संबंधी रूकावट से वैश्विक वित्तीय प्रणाली धराशायी होने के कगार पर पहुंच गई। वैश्विक मांग में कमी से वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई। तेल की कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई और खाद्य तथा अन्य वस्तुओं की कीमतों में भी इसी प्रकार की गिरावट आई। उभरते इक्विटी बाजारों में स्थानीय मुद्रा की दृष्टि से उनके एक तिहाई मूल्य का और अमेरिकी डालर की दृष्टि से उनके 40 प्रतिशत मूल्य का नुकसान हुआ।

### व्यापक अपगमन

- सन्निकट, मंदी को देखते हुए यूएस फेडरल रिजर्व और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ऋण बाजारों में 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डालर डाल दिया। अमेरिका ने बैंकों से विवादास्पद परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए सार्वजनिक निधियों का इस्तेमाल करने हेतु आर्थिक प्रोत्साहन विधान पारित किया और अनेक यूरोपीय देशों ने वित्तीय क्षति के प्रबंधन हेतु प्रोत्साहन पैकेजों का कार्यान्वयन किया।

### व्यापक अपगमन

पूरे विश्व के नीति निर्माताओं ने वित्तीय स्थिति को स्थिर करने की डरावनी चुनौती का सामना किया और साथ ही धीमी वृद्धि और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने की अवधि के दौरान अपनी अर्थव्यवस्थाओं की देखभाल की। बहुपक्षीय प्रयास विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। इस अवधि के दौरान चीन की भू-राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण रूप से बढ़ोतरी हुई। चूंकि जी-8 सदस्य देशों ने संकट का सामना किया था, अतः यह महत्वपूर्ण था कि इसके अधिदेश और संपत्ति को देखते हुए चीन की चर्चा में शामिल किया जाना पड़ा। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के प्रतिनिधित्व वाले जी-20 फ्रेमवर्क और यूरोपीय संघ वैश्विक संकट को दूर करने वाले समन्वयनकर्ता निकाय बन गए।

### व्यापक अपगमन

- नीतिगत कार्यों में जल्द परिसंपत्तियों को खरीदने, बैंकों के पुनर्पूजीकरण हेतु सार्वजनिक निधियों का प्रयोग करने और समेकित गारंटी प्रदान करने तथा प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतिगत दरों में समन्वित कमी लाने के कार्यक्रम शामिल थे।
- विकसित अर्थव्यवस्थाओं तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में शीघ्रता से धीमी होती आर्थिक गतिविधि के कारण मुद्रास्फीति के दबाव में नरमी देखी गई।
- विनियामक और पर्यवेक्षी अवसंरचना में अंतरालों को भरने के लिए बहुपक्षीय प्रयास आरंभ किए गए।

**व्यापक अपगमन**

चूंकि व्यापक नीतिगत मध्यस्थता ने मांग का समर्थन किया और वित्तीय प्रणाली के सर्वांगी जोखिम की अनिश्चितता को कम किया। अतः अक्टूबर 2009 तक आर्थिक विकास सकारात्मक रहा। हालांकि समुत्थान की गति धीमी थी, अतः वस्तुओं की कीमत पुनः उसी स्तर पर आ गई, विनिर्माण में तेजी आई और आवास संबंधी बाजारों में सुदृढ़ विश्वास के साथ उपभोक्ता के विश्वास की वापसी हुई।

**व्यापक अपगमन**

- विकसित अर्थव्यवस्थाओं और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं जिन्होंने मांग का समर्थन किया और वैश्विक मंदी के डर को समाप्त किया, में सुदृढ़ सावर्जनिक नीतियों के कारण वापसी हुई। केंद्रीय बैंकों ने अपवादात्मक रूप से दर में बड़ी कटौती के साथ प्रतिक्रिया की और सरकारों ने प्रमुख राजकोषीय प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किए। 2009 के अंत में प्रमुख नीतिगत चुनौती सुधार के सुदृढ़ धरातल पर आने तक समर्थनकारी बृहत् आर्थिक नीतियों को बनाए रखने की थी।

**व्यापक अपगमन**

- अप्रैल, 2010 तक वैश्विक जीडीपी वृद्धि के अत्यधिक अनुकूल मौद्रिक नीतियों और सहायक राजकोषीय नीतियों के आधार पर 4½ प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। प्रत्याशा से बेहतर सुधार हुआ और वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसे चरण पर पहुंच गई जहां मौद्रिक अनुकूलता को विनिमय दर में मामूली वृद्धि के साथ सावधानी से खोला जा सकता है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार एवं पुनरुद्धार कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए पहली प्राथमिकता रही। इसे बाद के वर्षों में पूरा किया गया।

### यूरोपीय संकट 2010

- वर्ष 2010 में यूरोपीय संकट शुरू हुआ।
- यूरो मुद्रा क्षेत्र यूरोपियन सेंट्रल बैंक के मुद्रास्फीति अधिदेश के अत्यंत प्रतिबंधात्मक होने से काफी व्यापक और विविध हो गया था। क्षेत्रों में संसाधनों के स्थानांतरण हेतु कोई राजकोषीय तंत्र नहीं था।
- उभरते बाजार वाले यूरोपीय देशों के एक समूह को 2008-09 में वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ी। इस समूह में जॉर्जिया, हंगरी, आइसलैंड, लात्विया, यूक्रेन, अर्मेनिया, बोस्निया और हर्जगोविना, रोमानिया और सर्बिया शामिल थे।
- ग्रीस (2011, 2012), आयरलैंड (2010), पुर्तगाल (2011) और साइप्रस (2013) जैसे यूरो क्षेत्र संकट वाले देशों यूरो क्षेत्र के भीतर बृहत् चालू खाता असंतुलन के साथ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की बैलेंस शीट संबंधी अतिसंवेदनशीलता की समस्याओं का सामना किया।

### यूरोपीय संकट 2010

- ग्रीस में बेघर लोग सूप किचन की कतार में खड़े होने लगे, पेंशनधारक आत्महत्या करने लगे, रोगियों को दवाइयां उपलब्ध नहीं होने लगी, दुकानें बंद हो गईं और सफाई कर्मी डस्टबिनों से खाने की वस्तुएं चुनने लगे - इन स्थितियों ने युद्ध के बाद के यूरोप की लगभग याद दिला दी।
- 25 वर्ष से नीचे का प्रत्येक व्यक्ति बेरोजगार था।
- ग्रीस की अर्थव्यवस्था अत्यधिक सार्वजनिक ऋण और बाजार तक पहुंच में विफलता के कारण लड़खड़ा रही थी।
- उच्च राजकोषीय घाटों और विदेशी ऋण पर निर्भरता से मांग बढ़ी।

### यूरोपीय संकट 2010

- यूरो क्षेत्र में प्रवेश करने से ग्रीस को निम्न लागत का ऋण प्राप्त करने और 4 प्रतिशत की औसत वृद्धि के साथ घरेलू मांग को बढ़ाने में सहायता मिली।

- ग्रीस ने 2000-2008 की अवधि के लिए कर में कटौती, पारिश्रमिक पर अधिक व्यय और 7 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के साथ प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीतियां भी चलाई।
- हेल्थकेयर और पेंशन लागते जीडीपी के क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत पर अत्यधिक थीं। ग्रीस में व्यापार हेतु वातावरण अत्यंत बेकार, उच्च मुद्रास्फीति जो यूरोजोन के औसत से काफी ऊपर और निम्न उत्पादकता थी।
- अभिशासन प्रणाली घटिया, कोई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नहीं और सार्वजनिक क्षेत्र अत्यधिक अकुशल था।

210

### यूरोपीय संकट 2010

- ग्रीस के प्राधिकारियों ने प्रारंभ में राजकोषीय घाटे को कम करने जैसी अति-संवेदनशील समस्याओं के समाधान हेतु बड़े दुर्बल प्रयास किए।
- प्रयास युक्तियुक्त नहीं थे और राजकोषीय स्थायित्व के बारे में चिंताएं बाजार संवेदना के और कमजोर होने के साथ गहरी हो गईं। विदेशी निधिपोषण समाप्त हो गया और बैंकिंग प्रणाली में विश्वास की कमी हो गई।

211

### यूरोपीय संकट 2010

- रेटिंग एजेंसियों द्वारा सॉवरेन डायनग्रेड की रिपोर्टिंग की गई, गैर-निष्पादनकारी ऋणों में बढ़ोत्तरी हुई और बैंकों की व्यवहार्यता में गिरावट आई।
- ग्रीस विदेशी ऋण प्राप्त करने हेतु अपने राजकोषीय आंकड़ों की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा था।
- 2008 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के प्रतिशत से बढ़कर जीडीपी का 7.7 प्रतिशत हो गया और 2008 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.7 प्रतिशत से बढ़कर जीडीपी का 13.6 प्रतिशत हो गया।
- 2009 का सार्वजनिक ऋण से संबंधी आंकड़ा जीडीपी के 99.6 प्रतिशत से बढ़कर जीडीपी का 115.1 प्रतिशत हो गया।

### यूरोपीय संकट 2010

- ग्रीस को अपने राजकोषीय घाटे को कम करने, अपने ऋण अनुपात को घटाने और अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए एक सुदृढ़ और स्थाई समायोजन कार्यक्रम की आवश्यकता थी।
- ग्रीस के लिए 2010 में आई एम एफ की उधत व्यवस्था 28 बिलियन यूरो की थी और द्विपक्षीय कार्यक्रम सहायता ग्रीस के 15 यूरोजोन भागीदार देशों द्वारा यूरोपियन सेंट्रल बैंक कैपिटल में उनके शेयरों के अनुपात में प्रदान की गई।
- ग्रीस को 2012 में एक अतिरिक्त कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ी जिसकी राशि 30 बिलियन यूरो थी।
- ग्रीस कार्यक्रम का लक्ष्य बाजार पहुंच पुनः प्राप्त करने के लिए विश्वास और राजकोषीय धारणीयता प्राप्त करना, प्रतिस्पर्धात्मकता बहाल करना और क्षेत्र की स्थिरता का बचाव करना था।

### यूरोपीय संकट 2010

- यूरो क्षेत्र में इस अप्रत्याशित संकट ने आयरलैंड और पुर्तगाल को भी प्रभावित किया।
- आयरलैंड में इस वैश्विक संकट का आयरिश बैंकिंग क्षेत्र पर प्रमुख अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा।
- इसके साथ-साथ रियल एस्टेट बाजार में बुलबुला फूटा जिसके परिणाम स्वरूप 41 प्रतिशत निवेश धराशायी हो गया और गंभीर आर्थिक मंदी आ गई जिससे बैंकों की हानि बढ़ गई और बैंकों के लिए थोक वित्तपोषण प्राप्त करने में कठिनाइयां बढ़ने लगीं।
- बाजार निधि पोषण तक पहुंच की कमी हो गई और कॉर्पोरेट द्वारा थोक जमा राशियों का बड़ा बहिर्प्रवाह हो गया, बैंक परिपक्व हो रही देयताओं के स्थान पर सेंट्रल बैंक निधिपोषण पर भरोसा करने लगे। आयरलैंड का एक्सपोजर यूरोपियन सेंट्रल बैंक के माध्यम से 90 बिलियन यूरो और सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड के माध्यम से 150 बिलियन यूरो का रहा।
- आइरिस प्राधिकारियों द्वारा की गई प्रारंभिक संकट की प्रतिक्रिया अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए अपर्याप्त थी और आयरलैंड को 22.5 बिलियन यूरो के आईएमएफ कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ी।

### यूरोपीय संकट 2010

- ग्रीस और आयरलैंड में इस संकट की पृष्ठभूमि में और यूरो क्षेत्र में संक्रमण के डर से पुर्तगाल को भी 2011 में वित्तीय क्षेत्र में अकस्मात गिरावट का सामना करना पड़ा।
- पुर्तगाल जब यूरो क्षेत्र में शामिल हुआ तो संस्थापक सदस्य देशों के बीच इसकी न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय थी। यूरो के आगमन के साथ आसान वित्त पोषण से व्यय में तेजी आई और ऋण अत्यधिक हो गया।
- पुर्तगाल यूरोपीय संघ की स्थिरता और विकास संधि के राजकोषीय नियमों का पालन करने में असफल रहा।
- 2010 तक जब वित्त पोषण समाप्त होने लगा तो पुर्तगाल को जीडीपी के 10% का चालू खाता और राजकोषीय घाटा हुआ और सार्वजनिक और निजी ऋण यूरो क्षेत्र में सबसे अधिक था।
- पुर्तगाल को 26 बिलियन यूरो के आईएमएफ वित्त पोषण कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ी।

### यूरोपीय संकट 2010

- यूरो क्षेत्र में संकट वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में अप्रत्याशित रूप में आया, इसके संक्रमण का जोखिम अत्यधिक था।
- प्रमुख चुनौतियों में बाजार पहुंच की अचानक हानि, बड़े असंतुलों और विनिमय दर नीतियों के लिए कोई सहारा न होने वाले देशों में व्यवस्थित समायोजन की आवश्यकता और यूरो क्षेत्र के फ़ायरवॉल का अभाव शामिल था।
- स्थिरीकरण कार्यक्रम फ़ायरवॉल तैयार करने हेतु समय प्रदान करने, संकट को फैलने से रोकने और विकास और बाजार पहुंच पुनः प्राप्त करने में सफल रहे।
- यूरो क्षेत्र एक साथ आईएमएफ की सफल गाथा, अंतरराष्ट्रीय भागीदार और कार्यक्रम से संबंधित देशों का प्रतिनिधित्व करता है।

**निष्कर्ष**

- पहले विश्व युद्ध के पूर्व अत्यधिक विश्वसनीय स्वर्ण मानक ने दीर्घावधिक विनिमय दर स्थिरता प्रदान की और विनिमय दर के जोखिम को समाप्त किया। अक्टूबर 1929 की महामंदी में अमेरिका और यूरोप में विदेशी पूंजीगत प्रवाह अचानक से बंद हो गया। चूंकि पाउंड का अवमूल्यन हो गया, अतः बड़े पैमाने पर पूंजी गायब हो गई परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन, विनिमय रोक, पूंजी पर नियंत्रण और व्यापार रुकावट जैसी घटनाएं हुईं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 उसके पश्चात मुद्रा कोष का गठन किया गया और चुनौतियों को दूर करने के लिए नियम तैयार किए गए।

**निष्कर्ष**

- 1972 तक ब्रिटेन वुड्स करार धराशाई हो गया था और आईएमएफ के करार के अनुच्छेदों में अनियत विनिमय दरों को विधिसम्मत बनाने हेतु संशोधन किया गया। अनियत विनिमय दरों के पहले 20 वर्ष विकसित अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों के बीच असंतुलन उत्पन्न होने के कारण निराशाजनक रहे। पूंजी खाता संकट 1994 में मेक्सिको, 1996/97 में एशियाई देशों, 1998 में रूस, 1999 में ब्राजील और 2002 में अर्जेंटीना जैसे अनेक उभरते बाजार देशों में 1990 से 2000 के दशकों में देखा गया।

**निष्कर्ष**

- 2000 के दशक के प्रारंभ में आई एम एफ दुविधा में था। निम्न आय वाले देशों को दिए जा रहे रियायती ऋण को छोड़कर कोई अन्य देश ऋण की मांग नहीं कर रहा था। अमेरिका को बड़ा घाटा हो रहा था जबकि चीन, जापान और जर्मनी के पास वृहत चालू खाता अधिशेष था। व्यापक अपगमन 2008 में हुआ। व्यापक अपगमन के दौरान महामंदी के जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिर पूंजी प्रवाह, मुद्रा भंडारों के लिए संघर्ष, समायोजन का विषम बोझ, दीर्घकालिक गतिहीनता और मुद्रा संबंधी युद्धों के बारे में चिंताएं देखी गईं।

### निष्कर्ष

- महामंदी और व्यापक अपगमन के बीच काफी समानताएं हैं। बेरोजगारी, आर्थिक निराशा और सामाजिक तनाव से उत्पन्न होने वाली कई चुनौतियां हैं और ये सभी वित्तीय संकट का परिणाम हैं। आज के मुद्रा संबंधी युद्ध 1930 के दशक के मुद्रा अवमूल्यन, विनिमय दर प्रतिबंध और अवरोधों से मिलते जुलते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली में देखे गए वर्तमान मुद्दे हैं - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडारों के लिए संघर्ष, दीर्घकालिक गतिहीनता का जोखिम और दीर्घकालिक गतिहीनता का विश्व। विश्व में मुद्रा संबंधी युद्ध अतीत में भी हुए थे।
- अपनी सीमाओं में मौद्रिक नीति, अत्यधिक ऋण से लड़खड़ाई हुई राजकोषीय नीति और राजनीतिक प्रतिबंधों के साथ मुद्रा अवमूल्यन के जरिए कुल मांग को बढ़ाएं जाने की अत्यंत आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय नीति के समन्वयन के मुद्दों के लिए वर्धित बहुपक्षीय प्रयास की आवश्यकता है।

### धन्यवाद